मोदी सरकार के 3.0 बजट पर मंत्रियों व नेताओं की प्रतिक्रिया

केंद्रीय बजटः मध्यम वर्ग के हित में क्रांतिकारी निर्णयः देवड़ा

भोपाल (काप्र)।

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 का बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने का रोडमैप है।

श्री देवडा ने कहा कि 12 लाख रूपये तक की सालाना आय पर आयकर न लगाकर एक बड़े वर्ग को राहत दी है। यह श्री मोदी की सरकार का क्रांतिकारी कदम है। श्री देवड़ा ने कहा कि यह बजट हर नागरिक के सपनों का बजट है। यह पूरी तरह प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के ज्ञान के मंत्र पर आधारित बजट है, जो गरीब कल्याण, युवा कल्याण, नारी शक्ति और किसानों की समृद्धि पर केंद्रित है। बजट में कई ऐसे अनूठे प्रावधान किए गए हैं, जिससे मध्यप्रदेश जैसे तेजी से आगे बढ़ते राज्य को मदद मिलेगी। बजट से विकास की प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और समावेशी विकास मजबूत होगा। निजी क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। श्री देवड़ा ने विशेष पूंजीगत सहायता को 1.50 लाख करोड़ रूपये से निरंतर रखने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मध्यप्रदेश को विशेष लाभ होगा। पूंजीगत सहायता का रचनात्मक उपयोग करने में मध्यप्रदेश का अच्छा प्रदर्शन रहा है। उन्होंने कहा कि यह बजट मुख्य रूप से कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को मजबूती देने वाला बजट है। भारत की विकास यात्रा के यही चार मुख्य स्तंभ है। इससे मध्यप्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन चारों क्षेत्रों में मध्यप्रदेश ने अभूतपूर्व काम किया है। श्री देवडा ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन जिलों में कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा, जो कई कारणों से पीछे रह गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने दलहन में आत्म-निर्भरता मिशन प्रारंभ करने की पहल का भी स्वागत करते हुए कहा कि दलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में आगे है। इसका फायदा मध्यप्रदेश को मिलेगा। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण की सीमा 3 लाख रूपये से बढ़कर 5 लाख रूपये करने का भी स्वागत करते हुए कहा कि इससे लाखों किसानों को मदद मिलेगी।

केंद्रीय बजट समावेशी और प्रगतिशीलः शुक्ल

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को समावेशी और प्रगतिशील केंद्रीय बजट (वर्ष 2025-26) प्रस्तुत करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह बजट भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और कर सुधारों में व्यापक कदम उठाए गए हैं, जो सभी वर्गों को लाभान्वित करेंगे।

श्री शुक्ल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने उन्नत चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में वृद्धि से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन से राज्य के अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्राप्त होगी।

हर वर्ग के लिए राहत और अवसरों का विस्तारः राजपूत

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आम बजट को सभी वर्गों के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि इस बार बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है। गरीब, युवा और महिलाओं के लिए कई योजनाओं के जरिए सरकार ने यह संकेत दिया है कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यह बजट विशेष रूप से मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यवसाय और छात्रों के लिए आशा की किरण है, वो इसे अपनी उम्मीदों को पूरा करने का एक अवसर मान रहे हैं।

कैंसर की दवाएं सस्ती करना केन्द्र सरकार का बड़ा कदमः श्री राजपूत ने कहा कि केन्द्र सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। इसका सीधा लाभ देश-प्रदेश की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले वित्त वर्ष में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।

विकास और कल्याण मूलक : सारंग

सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने केन्द्रीय बजट 2025-26 को विकास और कल्याण मूलक बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट ज्ञान पर ध्यान मंत्र को साकार करता है और देश के हर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सारंग ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग—गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बजट को युवाओं और गरीबों के उवल भविष्य की नींव बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल देश के समग्र विकास को गति देगी और भविष्य की पीढ़ियों को आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार को इस दूरदर्शी बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगाः तोमर

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बजट को अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार होगा। श्री तोमर ने कहा कि बजट देश को सशक्त बनाएगा। यह बजट किसान, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए है और उनके हितों की रक्षा करेगा। यह बजट औद्योगिक क्रांति लाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय में दी गयी इन्कम टैक्स की छूट का स्वागत किया है। जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती करने पर केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है।

गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए कल्याणकारी बजट : कंषाना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण एवं विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के कल्याण के लिए केन्द्रीय बजट 2025-26 में कई प्रावधान किए गए हैं। किसानों के हित में विभिन्न कल्याणकारी सौगातें देकर सराहनीय कार्य किया गया है। केन्द्रीय बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। अब किसानों को 5 लाख तक का ऋण क्रेडिट कार्ड से मिल सकेगा। यह बात किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने केन्द्रीय बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही। श्री कंषाना ने कहा कि प्रस्तुत बजट 2025-26 विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। यह कल्याकारी, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट देश के युवा, गरीब, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

सामाजिक न्याय और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा वाला हैः कुशवाह

सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि 2024-25 को केन्द्रीय बजट देश के सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट सरकार की गरीबी और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि बजट में केन्द्र सरकार फल-सब्जियों सहित अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम का प्रावधान स्वागत योग्य है।

बजट, विकसित भारत का रोडमैपः अहिरवार

वन राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि यह बजट विकसित भारत का रोडमैप है। मध्यम वर्ग के लिये बड़ी सौगात दी गई है। श्री अहिरवार ने कहा कि 12 लाख रूपये तक की वार्षिक आय को करमुक्त करने का निर्णय सराहनीय है। श्री अहिरवार ने कहा कि बजट जनहितैषी इसमें सर्वहारा वर्ग का ध्यान रखा गया है। विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना, (ग्रामीण) में अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घरों का निर्माण, लखपति दीदी के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिये टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा।

भारत नए बजट से बनेगा क्लीन एनर्जी का सिरमौरः शुक्ला

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ल ने बताया कि बजट 2025-26 प्रावधानों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत को नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विश्व का सिरमौर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री शुक्ला ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग मिशन के अंतर्गत सोलर पीवी सेल, ईवी बैटरीज, मोटर्स एंड कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर, विंड टरबाइंस, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण एवं ग्रिड स्केल बैटरी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सोलर मॉड्यूल पर लगाई जा रही कस्टम ड्यूटी को मौजूदा 40 प्रश से घटाकर 20 प्रश किया गया है। इससे सौर ऊर्जा के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। श्री शुक्ल ने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के गठन के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इससे क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे।

मील का पत्थर साबित होगा : डॉ नरोत्तम

पूर्व गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आम बजट को विकसित भारत के पथ का मील का पत्थर बताया है। डॉ मिश्रा ने कहा कि गरीब,मध्यम वर्ग की चिंता करने वाला यह बजट यथार्थ में प्रधानमंत्री के समृद्ध भारत के विजन का एक दस्तावेज है। बजट में सभी वर्ग के हितों को संरक्षित किया गया है। डॉ मिश्रा ने कहा कि बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और महिला वर्ग के उत्थान के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया है। हर वर्ग की चिंता कर गरीब, महिला, किसान और नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाते हुए 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है, वही फसलों की उपज बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना का शुभारंभ कर किसानों को लाभ पहुंचाकर किसान को समृद्ध करने का काम किया गया है।

जनविरोधी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट : पटवारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट आम जनता के लिए निराशाजनक और पूंजीपतियों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि देश पहले ही गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के संकट से गुजर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इस बजट में जनता को कोई राहत नहीं दी। श्री पटवारी ने कहा कि देश का किसान पहले से ही बदहाल स्थिति में है, लेकिन फिर भी इस बजट में किसानों के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें कोई अवसर देने की बजाय केवल आंकड़ों की बाजीगरी की है। उन्होंने कहा कि यह बजट उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग को इसमें कोई राहत नहीं दी गई। महंगाई चरम पर है, आवश्यक वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।

विकसित भारत के अटल संकल्प को पूरा करने वाला बजटः विष्णुदत्त

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट ऐतिहासिक और आम जनता को खुश करने वाला बजट है। यह विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। यह देश की अर्थव्यवस्था के नये आयाम को स्वरूप देगा। इस बजट में हमारे गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को सशक्त व सक्षम बनाने के प्रावधान किए गए हैं। इसमें एक तरफ जहां शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, वहीं मेडिकल एजुकेशन और आईआईटी में 75 हजार सीटें बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा की गई है, जिससे देश के 100 जिले और 1.70 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही मध्यम वर्ग को

बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है, जो एक ऐतिहासिक निर्णय है। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने बजट का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया है।

मध्यम वर्ग की बढ़ेगी शक्तिः श्री शर्मा ने कहा कि नए केंद्रीय बजट का फोकस विकास में तेजी लाने, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू खर्च में वृद्धि और देश के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने पर है। इस बजट में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, आवश्यकता होने पर 4 साल का इन्कम टैक्स रिटर्न एकसाथ फाइल किया जा सकेगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

अंबानियों और आडानियों को समर्पित बजटः माकपा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश बजट कारपोरेट घरानों के मुनाफों को बढाने और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही देश के प्राकृतिक संसाधनों को उनके हाथों में और तेजी से पहुंचाने वाला बजट है। इसलिए यह बजट पूरी तरह से अंबानियों और आडानियों को समर्पित बजट है। उक्त बात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने प्रेस केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही हैं। जसविंदर सिंह ने कहा कि इसमें मध्यम वर्ग को भलें ही आयकर मे छूट दी गई है लेकिन महंगाई के बेलगाम कर, नौकरियों के अवसरों को सिकोड़ कर वह भी उससे छीन लिया जाएगा। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लाखों पदों को भरने की बात न करना सरकार की नीयत को साफ कर देता है कि वह रोजगार के नाम पर ताली ही पीट सकती है। माकपा नेता ने कहा कि किसानों की मांगों को न सिर्फ इस बजट में शामिल नहीं किया गया है बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे किसानों और ग्रामीण जनता से दुश्मनी निकाली गई है। यह बजट किसान मजदूर विरोधी बजट है।

जापानी संस्कृति से मध्यप्रदेश की समृद्धि तक...

जापान यात्रा में मध्यप्रदेश के विकास का नया अध्याय लिखा गयाः डॉ. यादव

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जापानी संस्कृति से परिचय लेकर वहां के निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने तक की चार दिवसीय जापान यात्रा अत्यंत सुखद एवं सफल रही।

निश्चित ही जापान की यह यात्रा मध्यप्रदेश में निवेश के नये आयाम गढ़ेगी और फरवरी में भोपाल में आयोजित होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सहयोगी देश के रूप में जापान की सहभागिता से दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। डॉ. यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि प्रदेश सरकार के असरदार प्रयास से यहां निवेश बढ़ रहा है। निवेश बढ़ने से प्रदेश के जन-जन की हर आस अब पूरी होगी। उन्होंने कहा कि जापान यात्रा में मध्यप्रदेश के विकास का नया अध्याय लिखा गया है। विगत 28 से 31 जनवरी 2025 तक मध्यप्रदेश की उन्नति के साथ राज्य को नई दिशा देने के लिए जो अभिनव प्रयास हुए हैं, वह राज्य के इतिहास में दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाले हैं।

जीआईएस-2025 में आने वाले निवेशकों और उद्योगपतियों का हार्दिक स्वागत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में 24-25 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेसटर्स समिट 2025 में भारत समेत विश्व के अनेक देशों से आने वाले निवेशकों, उद्योगपतियों और कम्पनियों का हृदय से स्वागत किया है। डॉ. यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों, अलौकिक पर्यटन स्थल, कुशल औद्योगिक नीतियों एवं निवेश की असीम संभावनाओं से युक्त मध्यप्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने को तैयार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अनंत संभावनाओं से समृद्ध अपना हृदय प्रदेश -मध्यप्रदेश में सभी अतिथियों का हृदय की गहराईयों से स्वागत है, अभिनंदन है।

इनोवेशन, स्मार्ट सॉल्यूशंस और स्टॉफ की...

कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकताः सिंह

भोपाल(काप्र)।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश में एक साथ विभाग की संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन प्रशासनिक अकादमी से प्रदेश के आठ संभागीय मुख्यालयों में एक साथ किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य नवीनतम तकनीकों, उनके उपयोग और लाभों पर ध्यान केंद्रित करना था।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से उपस्थित अभियंताओं को आधुनिक निर्माण तकनीकों से अवगत कराया गया, जिससे सड़क निर्माण की गुणवत्ता, स्थायित्व और पर्यावरण-अनुकूलता को बढ़ाया जा सके। इस कार्यक्रम में उप यंत्री से लेकर अधीक्षण यंत्री स्तर तक के लगभग 1760 अभियंताओं ने भाग लिया। राज्य स्तर से मुख्य अभियंताओं के आठ दल अलग-अलग संभागों में भेजे गए, जिन्होंने नवीन तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान किया। भोपाल संभाग में प्रशिक्षण का आयोजन प्रशासन अकादमी में किया गया, जिसमे लगभग 360 प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्य स्तर से मप्र सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता केपीएस राणा एवं मुख्य अभियंता बीपी बोरासी प्रशिक्षक के रूप में

शामिल हुए। श्री सिंह ने कार्यशाला को विडियो कांफ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कहा की आज के युग में, जब टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही है, तो इंजीनियर्स के लिए स्वयं को अपडेट रखना आवश्यक हो गया है। इनोवेशन, सस्टेने-बिलिटी और स्मार्ट सॉल्यूशंस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

श्री सिंह ने कहा कि लोक निर्माण से लोक कल्याण तक का मार्ग इंजीनियर्स से ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की नींव तभी रखी गई थी जब देश में इस विभाग का गठन हुआ और तब से लेकर आज तक, यह विभाग लगातार समाज के विकास में योगदान दे रहा है। श्री सिंह ने कहा कि इंजीनियर्स द्वारा निर्मित संरचनाएँ केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और आध्यात्मिक केंद्रों तक पहुँच इन्हीं संरचनाओं के माध्यम से होती है, जो लोक कल्याण की दिशा में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गठन लोक कल्याण के लिए हुआ है, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इंजीनियर्स को अपने कर्तव्यों को समझते हुए कार्य करना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि इंजीनियर्स को सजगता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए, इससे उनके द्वारा निर्मित संरचनाएँ गुणवत्ता और विशिष्टता का प्रतीक बनें। उन्होंने कहा कि विभाग आपके साथ खड़ा हैं, जिससे मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स का नाम देशभर में सम्मान के साथ लिया जाए।

प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी प्रशिक्षक अभियंताओं द्वारा उपस्थित अभियंताओं को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नवीनतम तकनीकों, उनके उपयोग और लाभों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसमें प्रमुख रूप से व्हाइट टॉपिंग तकनीक, जो सड़कों की उम्र 15-20 साल तक बढ़ाकर रखरखाव की आवश्यकता को कम करती है, तथा फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक, जो पुरानी सड़क सामग्री के पुनः उपयोग से किफायती और पर्यावरण -अनुकूल निर्माण सुनिश्चित करती है, शामिल थीं। अल्ट्रा-हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट से हल्की और मजबूत सड़कें व पुल बनाए जाते हैं, जबकि वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग सड़कों को अधिक टिकाऊ और प्रदूषण-मुक्त बनाने में सहायक होता है। इस प्रशिक्षण का मुख्य आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद विक्रांत तोमर के मार्गदर्शन में आयोजित ट्रेनिंग नीड असेसमेंट सत्र रहा। उन्होंने सरल प्रश्नों के माध्यम से प्रतिभागियों के विचारों को एकत्रित कर प्रशिक्षण आवश्यकताओं को समझा। इस सत्र का उद्देश्य विभाग के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क तैयार करना था।

ये प्रश्न मेंटी पोर्टल एवं गूगल फॉर्म के माध्यम से पूछे गए थे और क्यूआर कोड/लिंक सभी प्रतिभागियों के साथ शेयर किये गए थे। इन प्रश्नों में इंजिनियर्स द्वारा फेस की जा रही मुख्य चुनौतिया, पूर्व में आयोजित प्रशिक्षण, विभिन्न क्षेत्रों में इंजिनियर्स का तकनीकी कौशल, सॉफ्टवेयर/टूल्स के प्रशिक्षण की आवश्यकता, क्रॉस-फंक्शनल टीमों के साथ सहयोग, व्यवहारिक कौशल विकास, आदि से सम्बंधित प्रश्न सम्मिलित थे। इस सत्र में प्रतिभागियों ने खुल कर अपने विचार रखे।